भारतीय जनता पार्टी

(केंद्रीय कार्यालय)
11 अशोक रोड, नई दिल्ली–110001
दूरभाष : 233005700; **फैक्स** : 23005787

<u>सांसद, श्री अरूण शौरी द्वारा</u>
<u>रविवार, 19 अप्रैल, 2009 को नई दिल्ली में जारी प्रेस वक्तव्य</u>

भारत के काले धन को विदेशी बैंकों से वापस लाना ; कांग्रेस पार्टी अपने स्वयं के मकड़जाल में फंसी

भारत से लूटी गई धनराशि को वापस लाए जाने की मांग को देशभर से मिले भारी समर्थन से सुन्न हुई कांग्रेस पार्टी ने अपने आपको कई गुत्थियों में उलझा लिया है।

कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस बारे में 5 प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं :

- श्री आडवाणी जी चुनावों की पूर्व संध्या पर इस मामले को अब क्यों उठा रहे हैं ?
- जीई–20 बैठक इस मुद्दे को उठाने के लिए उचित मंच नहीं था।
- धनराशि के आंकड़ों के बारे में संदेह है।
- भाजपा सरकार ने **फेरा** की जगह **फेमा** क्यों लागू किया तथा इसके द्वारा अपराधों को शमनीय क्यों बनाया ?
- क्या आडवाणी जी अवैध धन रखने वाले लोगों को स्विटजरलैंड से किसी अन्य Tax Havens पर उड़ा ले जाने के लिए अनजाने में चौकन्ना तो नहीं कर रहे हैं ?
- जब राजग सत्तारूढ़ था तब वह इस बारे में क्या कर रहा था ? हर स्थिति में आंकड़ों के बारे में संदेह बना हुआ है।

ये प्रतिक्रियाएं कांग्रेस की हड़बड़ाहट दर्शाती हैं, क्योंकि इस पर थोड़े से भी चिंतन–मनन से वह स्थिति सामने आ जाएगी, जिसका बचाव नहीं हो सकता है।

- **"श्री आडवाणी जी चुनावों की पूर्व संध्या पर इस मामले को अब क्यों उठा रहे हैं ?"**

सच्चाई यह है कि आडवाणी जी ने प्रधानमंत्री जी को गत वर्ष अप्रैल में पत्र लिखकर इस मामले को उठाया था। वित्त मंत्री द्वारा उन्हें भेजे गए उत्तर में दर्शाया गया था कि सरकार का सिवाय कुछ कदम उठाने का बहाना करके इस बारे में कुछ भी और करने का इरादा नहीं था। इसके कुछ दिन बाद हम यह जानकर चौंके कि वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने तत्कालीन जर्मनी–स्थित भारतीय राजदूत को लिखा कि वे जर्मनी द्वारा लीशटैन्सटीन से प्राप्त सूची में भारतीयों के नाम उजागर किए जाने पर जोर न डालें, कहीं ऐसा न हो कि जर्मन इस बात का बुरा मान जाएं और यह निष्कर्ष निकाल लें कि उन पर दबाव डाला जा रहा है और उनकी ईमानदारी पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। (बाद में इस सूचना की पुष्टि इंडियन एक्सप्रेस द्वारा 31 मार्च, 2009 को प्रकाशित रिपोर्ट से हुई)।

अब क्यों ? इसका उत्तर यह है कि पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के गंभीर संकट में फंसे होने के बाद ऐसा करने का नायाब अवसर केवल अभी आया था। इस आर्थिक संकट ने जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और यूके जैसे देशों को मजबूर किया था कि वे जी–20 में नेतृत्व की भूमिका ग्रहण करें और Tax Havens से चोरी किए गए धन को वापस लाने की प्रतिज्ञा करें। भाजपा का विश्वास है कि भारत के लिए अपने धन को वापस लाने के लिए वैश्विक प्रयास में शामिल होने का यह उचित समय है।

- **"जीई–20 बैठक इस मुद्दे को उठाने के लिए उचित मंच नहीं था"**

ऐसा आत्म–सेवी युक्तिकरण कांग्रेस पार्टी के एक अधिवक्ता और प्रवक्ता द्वारा रिवाजी तौर पर सुझाया गया था। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी छुपे–छुपे ऐसा संकेत देने का प्रयास भी कर रही थी कि वस्तुतः प्रधानमंत्री ने जी–20 शिखर बैठक में यह मामला उठाया था, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रधानमंत्री द्वारा शिखर बैठक में अथवा शिखर बैठक के बाद हुई "प्रेस मीट" (Press Meet) में दिए गए ऐसे किसी बयान का संकेत नहीं दे सके, तब उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री मिस्टर गोर्डन ब्राउन द्वारा दिए गए डिनर के मौके पर प्रधानमंत्री के भाषण में इस मामले के पासिंग रैफरेंस की मौजूदगी बताकर संतोष प्राप्त कर लिया।

किसी भी तरह, यदि जी–20 शिखर सम्मेलन यह मामला उठाने के लिए उचित मंच नहीं था, तब जी–20 नेताओं ने 2 अप्रैल, 2009 को जारी विज्ञप्ति में पैरा 15 में "वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करने" के बारे में ऐसा कैसे कहा था कि वे असहयोगी क्षेत्राधिकारों, जिनमें Tax Havens शामिल हैं के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए कृतसंकल्प हैं। हम अपने सार्वजनिक वित्त और वित्तीय प्रणालियों को संरक्षित रखने के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं। बैंकिंग गोपनीयता का युग समाप्त हो चुका है। हमने नोट किया है कि ओईसीडी (OECD) ने आज उन देशों की सूची प्रकाशित की है, जिनको ग्लोबल फोरम ने कर सूचना के विनिमय हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विरूद्ध पाया था ?" क्या कांग्रेस पार्टी की नजर में शिखर सम्मेलन के अवसर पर अपनी विज्ञप्तियों में दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त करते समय वे भी अनुपयुक्त रूप में कार्य कर रहे थे ?

- **"धनराशि के आंकड़ों के बारे में संदेह है"**

जैसाकि कांग्रेस पार्टी की प्रथा रही है वह उस धनराशि के बारे में, जो भारत से लूटी गई है और Tax Havens में पड़ी हुई है, मूल प्रश्न पर आंकड़ों और अनुमानों की परिशुद्धता के बारे में प्रश्न उठाकर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। यह उसी तरह का विधिकवाद है, जिसको अपनाकर मिस्टर पी. चिदम्बरम और अन्य वैधीकरण करने वाले व्यक्तियों ने बोफोर्स से हुई लूट पर पर्दा डालने के लिए प्रयास किया था।

ओईसीडी ने स्वयं अप्रैल 2009 के शुरू में प्रकाशित लेखों–जोखों में उल्लेख किया था कि 1.7 ट्रिलियन से लेकर 11.5 ट्रिलियन डॉलर की धनराशि है, जो आज भी Tax Havens में कैद है। ओईसीडी के इस अनुमान को भारतीय प्रेस में व्यापक रूप से प्रचारित किया गया था। मूल बिन्दु यह है : चाहे धनराशि कोड़ियों बिलियन डॉलरों में हो, न कि आधा ट्रिलियन डॉलर में हो, फिर भी उसको भारत वापस क्यों नहीं लाया जाना चाहिए ? क्या उस धनराशि को ऐसे में भारत वापस लाया जा सकता है जब सरकार का रवैया पूरी तरह निकम्मेपन से भरा हुआ हो जैसाकि वर्तमान सरकार का है।

क्या जिस सरकार ने इटालवी, सत्ता दलाल, ओटैवियो, क्वात्रोची, जो बोफोर्स घोटाले में प्रमुख अभियुक्त है को धनराशि फ्रीज़ कर दिए जाने के बाद भी बैंक से बाहर ले जाने की अनुमति दे दी थी उस पर लूट की राशि जो स्विस बैंकों तथा अन्य Tax Havens पर जमा है, वापस लाने के लिए भरोसा किया जा सकता है ? क्या उस सरकार पर जिसने सीबीआई का क्वात्रोची के अर्जेन्टीना से बाहर जाने के लिए दुरूपयोग किया था, लूट की राशि को वापस लाने का भरोसा किया जा सकता है।

- **"भाजपा सरकार ने फेरा की जगह फेमा क्यों लागू किया तथा इसके द्वारा अपराधों को शमनीय क्यों बनाया ?"**

पुनः, कांग्रेस पार्टी अपने श्रोतागण की थोड़े समय की याददाशत पर निर्भर हो रही है। मामले की सच्चाई यह है कि फेरा के कठोर उपबंधों को बदलने के लिए कांग्रेस से अधिक कोई पार्टी जोर नहीं डाल रही थी। इन परिवर्तनों पर 1996 से विचार किया जा रहा था। कठोर उपबंधों को दूर किए जाने की मांग सबसे अधिक तेज श्री वी.पी. सिंह की सरकार के दौरान हुई थी जब कठिन परिस्थितियों में उद्योंगों के मालिकों से पूछताछ करने के लिए **फेरा** का प्रयोग किया गया था। जैसा कि उस समय की समाचार–पत्र रिपोर्ट स्वयं दर्शाती हैं, **फेमा** का प्रारूप, जिसे सरकार ने जुलाई 1998 में अनुमोदित किया था, उन्हीं बिन्दुओं के अनुसार तैयार किया गया था, जिन्हें पूर्ववर्ती वित्त मंत्री मिस्टर पी. चिदम्बरम के नेतृत्व में तैयार किया गया था।

निम्नलिखित पैराओं में कानून को बदलने के कारणों को सपष्ट रूप में उल्लिखित किया गया है :

"हाल ही तक हमारे यहां **फेरा** के नाम से ज्ञात कानून मौजूद था। इसका उद्देश्य देश की विनिमय मुद्रा रिजर्व को संरक्षित और प्रोत्साहित करना था। कहा जाता है कि स्वर्ग का रास्ता अच्छे इरादों के साथ प्रशस्त होता है। अनेक अच्छे इरादों के साथ तैयार किए गए कानूनों की तरह **फेरा** से कठिनाइयां पैदा हुईं। **फेरा** ने विदेशी मुद्रा में कालाबाजार की वृद्धि को हवा दी। **फेरा** ने आर्थिक शब्दकोष में नया शब्द 'हवाला' जोड़ दिया है।" अवैध विदेशी मुद्रा लेन–देनों ने सीमापार संबंध रखने वाले क्राइम सिंडिकेट को बढ़ाने में योगदान किया है।

"**फेरा** उत्पीड़न का साधन भी बन गया है। उत्तरोतर सरकारों ने **फेरा** को बनाए रखा तथा कोफेपोसा (COFEPOSA) और **सैफेमा** (SAFEMA) को अलग से जोड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार उन कड़े कानूनों का मान नहीं करते जो सामान्य समझ के विरूद्ध होते है। भारत की रिजर्व विदेशी मुद्रा बढ़ने की बजाय चिंताजनक दर पर कम हो गई। अच्छी बात यह हुई कि 31 मई 2000 को **फेरा** को अंतिम रूप से दफन कर दिया गया।

उक्त लेख का लेखक कौन था ? मिस्टर पी. चिदम्बरम के अलावा कोई और नहीं था, जिन्होंने 25 अगस्त, 2002 को इंडियन एक्सप्रेस में उक्त लेख लिखा।

- **"क्या आडवाणी जी अवैध धन रखने वाले लोगों को स्विटजरलैंड से किसी अन्य Tax Havens पर उड़ा ले जाने के लिए अनजाने में चौकन्ना तो नहीं कर रहे हैं ?"**

कांग्रेस पार्टी के एक अन्य अधिवक्ता द्वारा दिया गया अन्य चतुराईभरा बयान। क्या उन लुटेरों को जिन्होंने भारत की धनराशि Tax Havens पर छिपा दी है, उसके बाद भी सतर्क किए जाने की जरूरत है जब जर्मनी ने उनके नाम लीशटेन्सटिन से पिछले वर्ष ही प्राप्त कर लिए थे। क्या उन्हें उसके बाद फिर

भी सतर्क किए जाने की जरूरत है जब जर्मनी ने नाम चाहने वाली सरकार को नाम बताने की पेशकश की थी ? क्या उन्हें इसके बाद भी सतर्क किए जाने की जरूरत थी, जब अमेरिका ने इस वर्ष फरवरी में उनके नाम स्विटजरलैंड के प्रमुख बैंक यूबीएस से प्राप्त कर लिए थे। क्या उन्हें उसके बाद भी सतर्क किए जाने की जरूरत थी जब डॉ. मनमोहन सिंह सहित जी–20 के नेताओं ने Tax Havens से उनके नाम प्राप्त करने का संकल्प व्यक्त किया था। किन्तु कांग्रेस पार्टी में ऐसा भ्रम व्याप्त है और इसके अधिवक्ता इतने प्रतिभाशाली हैं, कि वे देशभर से उठ रही लूट की राशि को Tax Havens से वापस लाने की मांग को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं।

- **"जब राजग सत्तारूढ़ था तब वह इस बारे में क्या कर रहा था ? हर स्थिति में आंकड़ों के बारे में संदेह बना हुआ है"**

अच्छा होगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता पूछें कि राजग सरकार के उन लोगों के नाम उजागर करने के प्रयासों को जिन्होंने बोफोर्स जैसे रक्षा सौदों तक में देश को लूटा था, निष्फल करने के लिए उस दौरान कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी, इसके नेता, अधिवक्ता क्या कर रहे थे ?

फेरा की जगह **फेमा** लाते समय भी राजग सरकार ने सुनिश्चित किया था कि फेरा के अधीन अभियोजन फाइल करने के लिए दो वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जाएगा और उसने ऐसे लोगों के विरूद्ध 2000 केस फाइल किए थे, जिसमें फेरा के व्यपगत होने से पहले पूछताछ की जा रही थी। ऐसा करने का कारण – वह कारण जो कांग्रेस पार्टी के अधिवक्ताओं को अच्छी तरह ज्ञात था – यह था कि जब कोई अभियोजन फाइल किया जाता है तब उसे समकालीन कानून के अनुसार नयायनिर्णीत किया जाता है। ये वे ही हैं, जिनकी कांग्रेस पार्टी ने बाद में पैरवी नहीं की।

निष्कर्ष

असली लड़ाई आगे है : वह लड़ाई जो देश के हित में है, वह लड़ाई जिसे उन लोगों के नाम जानने के लिए लड़ा जाना है, जो Tax Havens में दर्ज हैं और वह लड़ाई जिसे लूटे हुए धन को वापस लाने के लिए लड़ा जाना है।

जैसा कि श्री आडवाणी ने जोर देकर कहा है देशभर में सर्वानुमति बन रही है। अन्य राजनीतिक दलों जैसे जद(यू), एआईडीएमके, सीपीआई(एम), एसपी और बीएसपी के नेताओं ने भी मांग की है कि सरकार Tax Havens से उन लोगों के नाम प्राप्त करने के लिए और धनराशि वापस लाने के लिए शिद्दत से प्रयास करे।

इधर–उधर के बहाने करने के बजाय कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि उसने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जबकि जर्मनी की सरकार ने उन लोगों के नाम बताने की पेशकश की थी, जो उसने स्वयं प्राप्त किए थे।

श्री आडवाणी ने अब भी कांग्रेस सहित सभी पार्टियों से आग्रह किया है कि वे मिलकर इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करें।

यह वही उद्देश्य है, जिसको राजग पुनः सत्ता मिलने पर प्राप्त करने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम करेगा।

(श्याम जाजू)
मुख्यालय प्रभारी